

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2150 / 2025

तबस्सुम बीबी

—अपीलार्थी

## बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्वा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
लेखराज तोसवड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.09.2023 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित राजकीय अल्पसंख्यक अवासीय बालिका विद्यालय, सरवाड (कैकडी) में एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्रदान करने के आदेश प्रदान किये गये थे। इसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 23.09.2023 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी की एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं समाप्त हो चुकी है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने पारिवारिक कारणों से अपने विभाग ने यह निवेदन किया कि वो प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहना चाहती है। अपीलार्थी के पैतृक शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने आदेश दिनांक 07.01.2025 पारित कर अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने के आदेश पारित किये है और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को यह निर्देश दिये कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर अपीलार्थी को मूल स्थान पर भेजा जाए। संयुक्त शासन सचिव के उक्त आदेश की पालना में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने आदेश दिनांक 15.01.2025 पारित कर सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देश

दिये कि अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति स्थान से मूल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त किया जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति पर सेवा समाप्त की जा चुकी है, फिर भी अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अपीलार्थी को अपने मूल विभाग के लिये कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने अन्य अभ्यावेदन दिनांक 07.02.2025 के द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव से निवेदन किया कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाए, परन्तु फिर भी अपीलार्थी को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जाने के पश्चात भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है, जो विधि विरुद्ध है। ऐसे में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को निर्देश दिये जाएं कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाए।
5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति उसके पैतृक विभाग द्वारा समाप्त की जा चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते प्रत्यर्थी संख्या-4 व 5 को निर्देश दिये जाते हैं कि इस आदेश के प्राप्ति के 7 दिवस के अन्दर अपीलार्थी को पैतृक विभाग के लिये कार्यमुक्त करें। प्रत्यर्थी संख्या-2 को निर्देश दिये जाते हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जावे।
6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)